सौराष्ट्र राज्य

बनाम

मेमन हाजी इस्माइल हाजी

(न्यायाधीश एस.आर.दास, सी.जे., एन.एच. भगवती और

एम. हिदायतुल्ला,)

राज्य का अधिनियम-भारत अधिराज्य द्वारा जूनागढ़ राज्य के प्रशासन का अधिग्रहण-ऐसे अधिनियम के पूरा होने से पहले प्रशासक द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण-यदि राज्य का कोई कार्य नगरपालिका न्यायालयों में न्यायोचित नहीं है।

मुकदमा, जिसमें से वर्तमान अपील उत्पन्न हुई, मूल रूप से प्रतिवादी द्वारा जूनागढ़ राज्य के खिलाफ लाया गया था, जिसे बाद में सौराष्ट्र राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इस घोषणा के लिए कि प्रशासक का अक्टूबर 1948 का आदेश, मुकदमे में अचल संपत्ति को फिर से शुरू करना अवैध, अन्यायपूर्ण और प्राकृतिक न्याय के सभी नियमों के खिलाफ था। दीवानी न्यायाधीश द्वारा वाद का फैसला सुनाया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा अपील में आदेश की पुष्टि की गई थी। इस अपील में निर्धारण के लिए एकमात्र बिंदु यह था कि क्या प्रशासक द्वारा फिर से शुरू करने का कार्य भारत सरकार की ओर से किया गया राज्य का कार्य था और इसमें राज्य के बाहर कोई विदेशी शामिल था और इसलिए, नगरपालिका न्यायालयों में न्यायसंगत नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने और उसकी धारा 7 के कारण सर्वोच्चता समाप्त होने के साथ, जूनागढ़ का नवाब संप्रभु बन गया, लेकिन नए अधिराज्य में शामिल होने के बजाय वह पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। भारतीय राज्यों पर श्वेत पत्र से यह प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने नवाब की परिषद के अनुरोध पर 9 नवंबर, 1947 को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन 20

जनवरी, 1949 तक औपचारिक रूप से इसका विलय नहीं किया और उस अवधि के दौरान प्रशासक ने कानून और व्यवस्था बनाए रखी और प्रशासन चलाया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि जूनागढ़ राज्य का प्रशासन ग्रहण करने में भारत अधिराज्य का कार्य राज्य का एक शुद्ध और सरल कार्य था और उस अधिनियम के पूरा होने से पहले प्रशासक द्वारा प्रश्नगत बहाली की गई थी और ऐसे समय में जब प्रतिवादी सहित जूनागढ़ के लोग राज्य के बाहर विदेशी थे, बहाली का कार्य, चाहे कितना भी मनमाना क्यों न हो, भारत सरकार की ओर से राज्य का एक कार्य था और इसलिए, नगरपालिका न्यायालयों में न्यायसंगत नहीं था।

ऐसे मामलों में परीक्षण यह होना चाहिए कि क्या राज्य या उसके एजेंटों ने "विनाशकारी" कार्य करने का इरादा किया है या कानून के सामान्य पाठ्यक्रम के अधीन है।

सलमान बनाम भारत के लिए राज्य सचिव, (1906) के.बी. 613, जॉनस्टोन बनाम पेडलर, (1921) 2 ए.सी. 262, भारत के लिए परिषद में राज्य सचिव बनाम कामची बोये सहाबा, (1859) 13 मूर पी.सी. 22, वजे सिंह जी जोरावर सिंह और अन्य बनाम भारत के लिए राज्य सचिव, (1924) एल.आर. 51 आई.ए. 357, डालमिया दादरी सीमेंट कंपनी बनाम आयकर आयुक्त, (1959) एस. सी. आर. 729, पर भरोसा किया।

वनपाल और अन्य बनाम भारत के राज्य सचिव, 18 डब्ल्यू. आर. 349 पी.सी., पर विचार किया गया।

राज्य के एक अधिनियम का सार नगरपालिका कानून के अलावा या सर्वोपरि सिद्धांतों पर संप्रभु शक्ति का मनमाना प्रयोग था। यद्यपि संप्रभु निवासियों को अपने पुराने कानूनों और रीति-रिवाजों को बनाए रखने की अनुमति दे सकता है, लेकिन यह

स्वयं उनके द्वारा तब तक बाध्य नहीं हो सकता जब तक कि यह उनके भीतर कार्य करने का इरादा नहीं रखता है, इस प्रकार राज्य के कार्य को समाप्त कर देता है।

कैम्पबेल बनाम हॉल, आई. कॉम्प. 204; 98 ई.आर. 1045, रूडिंग बनाम स्मिथ, 2 हैग। कोन. 384; 161 ई.आर. 774 और ई.आई. कंपनी बनाम सैयद अली, 7 एम. आई. ए. 555, संदर्भित।

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील संख्या 185/1955।

सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, जूनागढ़ के 1950 के सिविल सूट संख्या 470 में 15 दिसंबर, 1951 के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न 1952 की सिविल प्रथम अपील संख्या 16 में पूर्व सौराष्ट्र उच्च न्यायालय के 19 फरवरी, 1953 के निर्णय और डिक्री से अपील।

अपीलार्थी की ओर से भारत के सॉलिसिटर-जनरल जी.के. डाफ्टरी, आर. गणपति अय्यर और डी. गुप्ता ने भाग लिया।

आई.एन. श्रॉफ, प्रत्यर्थी के लिए।

मध्यस्थता वालों के लिए एच.जे. उमरीगर और के.एल. हाथी।

1959 अगस्त 4 को न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला द्वारा सुनाया गया।

नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 109 और 110 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत सौराष्ट्र के पूर्व उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र के साथ यह अपील उस न्यायालय के 19 फरवरी, 1953 के फैसले के खिलाफ 1952 की सिविल प्रथम अपील संख्या 16 में लाई गई है।

अपीलकर्ता सौराष्ट्र राज्य है, जो जूनागढ़ राज्य के स्थान पर खड़ा हुआ था, जिसके खिलाफ मूल रूप से याचिका दायर की गई थी। प्रतिवादी, जूनागढ़ के मेमन हाजी इस्माइल हाजी वलीमाहोमेड (बाद में प्रतिवादी के रूप में संदर्भित), यह मुकदमा मूल रूप से दो प्रतिवादियों, जूनागढ़ राज्य और एक जमादार अबू उमर बिन अब्दुल्ला के खिलाफ लाया गया था।

अबू पंच (इसके बाद अबू पंच के रूप में संदर्भित), इस घोषणा के लिए कि 1 अक्टूबर 1948 का सचिवालय आदेश संख्या 2/3289, "अवैध, अन्यायपूर्ण और प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध" था। उन्होंने एक वैकल्पिक राहत के लिए भी कहा कि दूसरा प्रतिवादी उसे 30,000 रुपये से अधिक 541-2-0, रुपये की राशि वापस करे। उक्त आदेश के तहत फिर से शुरू की गई अचल संपत्ति के हस्तांतरण का विचार और व्यय। दीवानी न्यायाधीश द्वारा वाद का फैसला सुनाया गया था, जिन्हें एकीकरण के बाद मामला स्थानांतरित कर दिया गया था, और उच्च न्यायालय द्वारा अपील के तहत निर्णय द्वारा डिक्री की पुष्टि की गई थी। यह इंगित किया जा सकता है कि इस मुकदमे के दौरान, एक तीसरे प्रतिवादी, अर्थात् मामलातदार, विश्वदार को भी फंसाया गया था, क्योंकि अबू पंच की संपत्ति सौराष्ट्र सरकार के प्रबंधन में चली गई थी, जिसे मामले में घरखोद अध्यादेश के रूप में वर्णित किया गया है। यह आगे बताया जा सकता है कि सौराष्ट्र राज्य के अलावा दो प्रतिवादियों को मुकदमे से बरी कर दिया गया था, और यह केवल ऊपर वर्णित घोषणा की राहत के लिए सौराष्ट्र राज्य के खिलाफ आगे बढ़ा।

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं: एक अमीर इस्माइल खोखर कायम खोखर ने जूनागढ़ राज्य से जूनागढ़ शहर में जमीन का एक भूखंड खरीदा और उस पर एक घर बनाया। 2 दिसंबर, 1939 को उन्हें एक रुक्का जारी किया गया था, जो वादी की प्रदर्शनी संख्या 34 है। वर्ष 1941 में, जूनागढ़ के नवाब ने खोखर से संपत्ति खरीदी थी, हालांकि यह खरीद किसके द्वारा की गई, मामले में इसका दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया

गया है। 17 नवंबर 1941 को नवाब ने यह संपत्ति अबू पंच को उपहार में दे दी। अबू पंच ने 24 नवंबर, 1943 को प्रतिवादी को संपत्ति 30,000 रुपये में बेच दी। मूल उपहार विलेख (वादी के 18 मई, 1942 के प्रदर्शन में वर्णित) में संपत्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दरअसल, 18 मई, 1942 के उक्त दस्तावेज़ में कहा गया था कि यह घर अबू पंच के "उपयोग और आनंद" के लिए दिया गया था। इसके बाद, 12 फरवरी, 1944 को, नवाब ने अबू पंच के लिए घर बेचना संभव बनाकर पैलेस ऑर्डर में कुछ संशोधन का आदेश दिया। इसे इस प्रकार बताया गया:

> "...आपको उपहार की तारीख यानी 17-11-41 से इस रूक्का में परिभाषित और प्राप्त निर्देशों के अनुसार घर बेचने का अधिकार दिया जाता है।"

ऐसा प्रतीत होता है कि यह अतिरिक्त शेरा उस बिक्री को मान्य करने के लिए जारी किया गया था जो पहले अबू पंच द्वारा की गई थी। हालाँकि, मामला इस प्रकार बना रहा जब स्वतंत्रता के बाद जूनागढ़ राज्य के मामलों में अराजकता फैल गई और राज्य परिषद के निमंत्रण पर भारत सरकार ने क्षेत्रीय आयुक्त, पश्चिमी भारत और गुजरात राज्य क्षेत्र को भारत सरकार की ओर से राज्य के प्रशासन का प्रभार संभालने का आदेश दिया। क्षेत्रीय आयुक्त ने 9 नवंबर, 1947 को एक घोषणा जारी की, जिसे 10 नवंबर, 1947 के विनाशकारी अमल सरकार जूनागढ़ में प्रकाशित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने भारत सरकार के आदेश के तहत 18:00 बजे जूनागढ़ राज्य के प्रशासन का कार्यभार संभाल लिया था। घोषणा जो संक्षिप्त है, यहाँ उद्धृत की जा सकती हैः

"आई, एन.एम. बुच, बैरिस्टर-एट-लॉ ओ.बी.ई., आई.सी.एस., क्षेत्रीय आयुक्त, पश्चिमी भारत और गुजरात राज्य क्षेत्र ने प्रशासन के पूरी तरह से टूटने के परिणामस्वरूप राज्य में अराजक स्थिति को देखते हुए जूनागढ़ के लोगों द्वारा समर्थित जूनागढ़ राज्य परिषद के अनुरोध पर भारत सरकार के आदेश के तहत आज 18.00 बजे जूनागढ़ राज्य के प्रशासन का कार्यभार संभाल लिया है। मेरा और मेरे अधिकारियों का पहला काम पूरे जूनागढ़ राज्य क्षेत्र में पूर्ण शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करना और सभी समुदायों को न्याय देना होगा। राज्य के बहुसंख्यक समुदाय की अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी है। इसलिए जूनागढ़ राज्य के सभी अधिकारियों और प्रजाओं को नए प्रशासन को बिना शर्त और वफादार समर्थन और सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लोगों के हित में और "शांति और व्यवस्था" के संरक्षण के लिए असहयोग और बेवफाई के किसी भी कार्य से निपटा जाना चाहिए और उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

जूनागढ़ एन.एम बूच

9 नवम्बर, 1947 क्षेत्रीय आयुक्त

पश्चिमी भारत और गुजरात

राज्य क्षेत्र"

14 नवंबर, 1947 को क्षेत्रीय आयुक्त ने एक अधिसूचना (1947 का 6 नंबर) द्वारा श्री एस. डब्ल्यू. शिवशंकर को जूनागढ़ राज्य का प्रशासक नियुक्त किया। वह अधिसूचना इस प्रकार थीः

"श्री एस. डब्ल्यू. शिवशंकर एम. बी. ई., आई. सी. एस. को पश्चिमी भारत और गुजरात राज्य क्षेत्र के क्षेत्रीय आयुक्त के सचिव के पद से मुक्त किए जाने पर, राव साहब टी. एल. शाह, बी. ए. के स्थान पर जूनागढ़ राज्य का प्रशासक नियुक्त किया गया है। मेरी पीढ़ी के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में प्रशासक को सभी आदेश पारित करने और जूनागढ़ राज्य के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा।

जूनागढ़ — एन.एम बूच

14 नवम्बर, 1947 — क्षेत्रीय आयुक्त

पश्चिमी भारत और गुजरात

राज्य क्षेत्र"

13 अक्टूबर, 1948 को श्री शिवशंकर ने सचिवालय आदेश सं. 1948 का आर/3289, जिसे मुकदमे में आरोपित किया गया था। इसमें लिखा हैः

> "वर्ग गज भूमि 1,846-9-12 उस पर भवन सहित, कार्यशाला के सामने मजेवड़ी गेट के बाहर स्थित, दिनांक 17 नवंबर 1941 निजी सचिव के कार्यालय संख्या पी 158 के तहत जूनागढ़ के अबू उमर बिन अब्दुल्ला अबू पंच को इनाम के रूप में उपहार के रूप में दी गई थी। दाता को रक्का नंबर 32/98 के तहत उक्त भूमि और इमारत को बेचने का कोई अधिकार नहीं था और विक्रेता सेठ हाजी इस्माइल हाजी वलीमहमद ने इसकी सामग्री की पूरी जानकारी के साथ इसे खरीदा था।
>
> यह अनुदान सार्वजनिक संपत्ति का एक अनुचित और अनधिकृत उपहार होने के कारण उपरोक्त आदेश एतदद्वारा रद्द कर दिया जाता है

और चूंकि बाद के खरीदार को दाता, श्री अबू पंच के स्वामित्व से अधिक कोई अधिकार, स्वामित्व या ब्याज नहीं मिलता है, इसलिए यह आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि जिस पर अधिरचनाएं हैं, राज्य द्वारा तुरंत राज्य की संपत्ति के रूप में फिर से शुरू की जानी चाहिए।

एस डब्ल्यू शिवेशवरकर

प्रशासक

राष्ट्रपति की कार्यकारिणी

परिषद, जूनागढ़ राज्य"

ऐसा प्रतीत होता है कि इसके तुरंत बाद प्रशासक ने इस संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया और वादी-प्रत्यर्थी ने जूनागढ़ राज्य सिविल प्रक्रिया संहिता (सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के अनुरूप) की धारा 423 के तहत नोटिस देने के बाद राज्य के उच्च न्यायालय में उपरोक्त घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मुकदमे को बाद में सिविल जज, सीनियर डिवीजन, जूनागढ़ को स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्होंने 15 दिसंबर, 1951 को घोषणा करने का आदेश दिया। उन्होंने माना कि प्रशासक का आदेश अवैध और निष्क्रिय था और "प्राकृतिक न्याय के सभी नियमों" के खिलाफ भी था। सौराष्ट्र राज्य द्वारा एक अपील दायर की गई थी, जैसा कि मुकदमे में ही किया गया था, कि श्री शिवशंकर की कार्रवाई, जो अतिरिक्त प्रांतीय क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत नियुक्त भारत सरकार के प्रतिनिधि थे, राज्य का एक अधिनियम होने के नाते न्यायोचित नहीं थी, कि सिविल कोर्ट की क्षेत्राधिकार को अतिरिक्त प्रांतीय क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 5 और 1949 के अध्यादेश संख्या 72 की धारा 4 (2) के तहत वर्जित किया गया था और अनुदान

हमेशा शासक द्वारा पुनः देय था और उत्तराधिकारी के रूप में श्री शिवशंकर भी इसे फिर से शुरू कर सकते थे।

सौराष्ट्र के उच्च न्यायालय ने कर्नल वेब के राजनीतिक अभ्यास में सर रेमंड वेस्ट द्वारा तैयार किए गए एक मिनट का विस्तार से उल्लेख किया, जिसमें लेखक ने कहा था कि उनके द्वारा दिए गए अनुदान को फिर से शुरू करने के लिए शासकों के क्या अधिकार थे और कहा था कि शासकों द्वारा इस तरह की बहाली संभव नहीं थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई को राज्य के अधिनियम के रूप में नहीं माना जा सकता है और आगे कहा कि न्यायालयों की अधिकारिता को न तो अतिरिक्त प्रांतीय क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 5 द्वारा और न ही 1949 के अध्यादेश संख्या 72 की धारा 4 (2) द्वारा बाधित किया गया था।

इस अपील में, सौराष्ट्र राज्य की ओर से विद्वान सॉलिसिटर-जनरल ने नीचे दिए गए न्यायालयों में उठाए गए तीन तर्कों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राज्य इस संपत्ति को फिर से शुरू करने के लिए जूनागढ़ के शासक के उत्तराधिकारी के रूप में श्री शिवशंकर की शक्ति पर भरोसा नहीं कर रहा था, और इसलिए सर रेमंड वेस्ट के कार्यवृत्त का कोई संदर्भ आवश्यक नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने फिर से शुरू करने को सही ठहराने की कोशिश नहीं की और न ही अतिरिक्त-प्रांतीय क्षेत्राधिकार अधिनियम और उपर्युक्त अध्यादेश के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। उन्होंने दलील दी कि श्री शिवशंकर की कार्रवाई भारत सरकार की ओर से किया गया राज्य का एक कार्य था, और इसलिए नगरपालिका न्यायालयों में न्यायसंगत नहीं था।

'राज्य का कार्य' शब्द के कई उपयोग और अर्थ हैं। फ्रांस और कुछ महाद्वीपीय देशों में राज्य और उसकी आधिकारिक क्षमता में कार्य करने वाले अधिकारियों के कार्य

सामान्य अदालतों द्वारा संज्ञान में नहीं आते हैं और न ही वे देश के सामान्य कानून के अधीन होते हैं। इस नियम का कारण यह बताया गया है कि सभी कानूनों के स्रोत के रूप में राज्य इसके अधीन नहीं हो सकता है। हमारी विधि प्रणाली में जो अंग्रेजी न्यायशास्त्र से विरासत में मिली है, यह स्वीकार नहीं किया जाता है और एक विशेष प्रकार के कुछ कार्यों को छोड़कर, अन्य सभी आधिकारिक कार्यों को कानूनी आधार होने के रूप में उचित ठहराया जाना चाहिए। इस अर्थ में 'राज्य अधिनियम' का अर्थ सभी सरकारी कार्य नहीं हैं जैसा कि फ्रांसीसी और महाद्वीपीय प्रणालियों में होता है, बल्कि उनमें से केवल कुछ ही हैं। इस शब्द का उपयोग प्रतिरक्षा और प्रतिबंधों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है जो कभी-कभी कानूनों द्वारा बनाए जाते हैं। इस कार्यकाल को आंतरिक सरकार के व्यवसाय में संप्रभु और उसके एजेंटों द्वारा प्राप्त कुछ विशेषाधिकारों और विशेष उन्मुक्तिओं को शामिल करने के लिए भी बढ़ाया गया है। इस शब्द का उपयोग उन सभी कार्यों को इंगित करने के लिए भी किया जाता है जिनमें, इस कारण से कि वे आधिकारिक हैं, अदालतें पूछताछ नहीं कर सकती हैं, या जिनके संबंध में एक आधिकारिक घोषणा अदालतों पर बाध्यकारी है।

हम इन और ऐसे अन्य अर्थों से चिंतित नहीं हैं। रक्षा राज्य के एक अधिनियम पर आधारित है जिसमें राज्य के बाहर एक विदेशी शामिल होता है। फ्लेचर मौल्टन, एल. जे. ने सलमन बनाम भारत के लिए राज्य सचिव (') में राज्य के इस तरह के कार्य को सुरुचिपूर्ण वाक्यांश में' एक नए प्रस्थान का गठन करने वाले विनाशकारी परिवर्तन 'के रूप में वर्णित किया था। यह एक संप्रभु अधिनियम है जो न तो कानून में आधारित है और न ही ऐसा होने का नाटक करता है। इस तरह के 'विनाशकारी परिवर्तनों' के उदाहरण युद्ध की घोषणाओं, संधियों, विदेशी देशों के साथ व्यवहार और राज्य के बाहर के विदेशियों में पाए जाते हैं। ऐसी कार्रवाइयों की वांछनीयता या न्याय पर नगरपालिका न्यायालय कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। नागरिक हंगामे में, या यहाँ

तक कि युद्ध या शांति में भी, राज्य सामान्य कानून के बाहर 'विनाशकारी' कार्य नहीं कर सकता है और अपनी प्रजा या यहां तक कि राज्य के भीतर एक दोस्ताना विदेशी के खिलाफ अपने गलत कार्यों के लिए कानूनी उपाय है। जॉनस्टोन बनाम पेडलर (2) देखें। लेकिन राज्य के बाहर किसी विदेशी के खिलाफ राज्य द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में अदालतों के हस्तक्षेप से प्रतिरक्षा है।

इस प्रकार सवाल हमेशा यह होता हैः क्या राज्य या उसके एजेंट 'विनाशकारी' कार्य करने का इरादा रखते थे या कानून के सामान्य पाठ्यक्रम के अधीन थे? यह सवाल लॉर्ड किंग्सडाउन द्वारा भारतीय परिषद में राज्य सचिव बनाम कामची बोये सहाबा (8) में इन शब्दों में पूछा गया थाः -

> "इस मामले में किए गए कृत्य का वास्तविक स्वरूप क्या था? क्या यह ग्रेट ब्रिटेन के क्राउन की ओर से किसी पड़ोसी राज्य के प्रभुत्व और संपत्ति की मनमानी शक्ति द्वारा कब्ज़ा था, एक ऐसा कार्य जो नगरपालिका कानून के आधार पर खुद को सही ठहराने के लिए प्रभावित नहीं कर रहा था? या यह, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, तंजौर के दिवंगत राजा की संपत्ति के कानूनी अधिकार के तहत क्राउन द्वारा लिया गया कब्जा था, उन लोगों के लिए विश्वास में, जो कानून द्वारा, अंतिम स्वामी की मृत्यु पर इसके हकदार हो सकते हैं? यदि यह बाद वाला था, तो निश्चित रूप से रक्षा व्यवस्था का कोई आधार नहीं है।"

उस मामले में मद्रास के सर्वोच्च न्यायालय ने तंजौर के राजा शिवाजी की मृत्यु पर जब्त की गई कुछ संपत्तियों पर दावा करने के लिए एक विधेयक पेश किया था।

इस दावे को मद्रास के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था लेकिन प्रिवी काउंसिल ने इसे खारिज कर दिया था। लॉर्ड किंग्सडाउन ने इस मामले में कहाः -

> "कानून के सामान्य सिद्धांत को किसी भी कारण के साथ विवादित नहीं किया जा सकता था। एक-दूसरे के बीच स्वतंत्र राज्यों के लेन-देन नगरपालिका न्यायालयों द्वारा प्रशासित कानूनों के अलावा अन्य कानूनों द्वारा शासित होते हैं। ऐसे न्यायालयों के पास न तो यह तय करने का साधन है कि क्या सही है और न ही उनके द्वारा किए गए किसी भी निर्णय को लागू करने की शक्ति है।"

यह तय करने के बाद कि राज्य का एक अधिनियम था, लॉर्ड किंग्सडाउन ने आगे कहाः

> "उस अधिनियम के औचित्य या न्याय के संबंध में, न तो निम्न न्यायालय और न ही न्यायिक समिति के पास कोई राय बनाने का साधन है, या व्यक्त करने का अधिकार है, यदि उन्होंने कोई राय बनाई थी। हो सकता है कि यह उन लोगों के लिए न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण, राजनीतिक या अनैतिक, लाभकारी या हानिकारक रहा हो, जिनके हित प्रभावित हुए हैं। ये ऐसे विचार हैं जिनमें उनके अधिपत्य प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि, भले ही कोई गलती की गई हो, यह एक गलत है जिसके लिए कोई भी नगरपालिका न्यायालय कोई उपाय नहीं कर सकता है।"

इसी तरह का विचार कुर्ग के राजा बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी (1) (1860) 29 बेव, 300) राजा सलीग्राम बनाम परिषद में भारत के राज्य सचिव (2) (1872) एल.आर. इण्डि. एप) पूरक वॉल्यूम 119) और सरदार भगवान सिंह बनाम राज्य सचिव (3)(1874) एल.आर. 2 ए.आई. केस 38) और राज्य सचिव बनाम सरदार रुस्तम खान (4)(1941)

एल.आर. 68 आई.ए. 109) में भी व्यक्त किया गया था। इन मामलों के सिद्धांत को सभी नए क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है, चाहे वे विजय, या विलय या समर्पण या अन्यथा द्वारा अर्जित किए गए हों और पिछली सर्वोच्च शक्ति द्वारा बनाए गए अधिकारों, अनुबंधों, रियायतों, उन्मुक्ति और विशेषाधिकारों के लिए भी। इन्हें उत्तराधिकारी शक्ति पर बाध्यकारी नहीं माना जाता है, भले ही विलय से पहले दोनों शक्तियों के बीच यह सहमति थी कि उनका सम्मान किया जाएगा। लॉर्ड डुनेडिन ने वजे सिंह जी जोरावर सिंह और अन्य बनाम भारत के राज्य सचिव [(5)](1924) एल.आर. 51 आई.ए. 357 ए 360) में कानून का सारांश इन शब्दों में दिया हैः

> "जब किसी संप्रभु राज्य द्वारा पहली बार किसी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है तो यह राज्य का एक कार्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अधिग्रहण कैसे किया गया। यह विजय द्वारा हो सकता है, यह संधि के बाद समर्पण द्वारा हो सकता है, यह किसी मान्यता प्राप्त शासक द्वारा अब तक के क्षेत्र पर कब्जा करके हो सकता है। सभी मामलों में परिणाम समान होता है। क्षेत्र का कोई भी निवासी नए संप्रभु द्वारा स्थापित नगरपालिका अदालतों में ऐसे किसी भी अधिकार को हासिल कर सकता है, जिसे उस संप्रभु ने अपने अधिकारियों के माध्यम से मान्यता दी है। पूर्ववर्तियों के शासन में उनके पास जो अधिकार थे, उनसे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इसके अलावा, भले ही समर्पण की संधि में यह निर्धारित किया गया हो कि कुछ निवासियों को कुछ अधिकारों का आनंद लेना चाहिए, जो उन निवासियों को नगरपालिका न्यायालयों में इन शर्तों को लागू करने का अधिकार नहीं देता है। लागू करने का अधिकार केवल उच्च संविदाकारी पक्षों के पास रहता है।"

इन मामलों और कुक बनाम स्प्रिग [1] (1899) ए.सी. 572), होनी ते हुहेउ टुकिनो बनाम आओटिया जिला माओरी भूमि बोर्ड [2](1941) ए.सी. 308) जैसे अन्य मामलों को इस न्यायालय द्वारा डालमिया दादरी सीमेंट कंपनी बनाम आयकर आयुक्त [3] (1959) एस.सी.आर. 729, 740-41) में अनुमोदित और लागू किया गया था जिसमें कर रियायतों के लिए झिंद के पूर्व शासक के साथ एक समझौता किया गया था जो भारत संघ के साथ राज्य के विलय के बाद आयकर अधिकारियों पर बाध्यकारी नहीं था और राज्य के एक अधिनियम के बचाव को बरकरार रखा गया था। न्यायाधीश वेंकटरामा अय्यर ने तब टिप्पणी कीः

"जब किसी राज्य का संप्रभु-उस अभिव्यक्ति का अर्थ, वह प्राधिकरण जिसमें राज्य की संप्रभुता निहित है, एक ऐसा कानून बनाता है जो विषयों में अधिकारों का निर्माण करता है, घोषणा करता है या उन्हें मान्यता देता है, तो उन अधिकारों का कोई भी उल्लंघन उस राज्य की अदालतों में कार्रवाई योग्य होगा, भले ही राज्य अपने अधिकारियों के माध्यम से कार्य कर रहा हो। यह उस कार्रवाई का कोई बचाव नहीं होगा कि जिस अधिनियम की शिकायत की गई है वह राज्य का एक कार्य है, क्योंकि संप्रभु और उसकी प्रजा के बीच राज्य का कोई कार्य नहीं है, और यह उसके अधिकारियों पर यह दिखाने के लिए बाध्य है कि उनकी कार्रवाई जो चुनौती के तहत है वह कानून द्वारा उन्हें दिए गए अधिकार के भीतर है। कुल मिलाकर अलग-अलग विचार तब उत्पन्न होते हैं जब संप्रभु के कार्य में उसकी प्रजा के अधिकारों का नहीं बल्कि दूसरे संप्रभु से संबंधित क्षेत्रों के अधिग्रहण का संदर्भ होता है। यह स्वतंत्र संप्रभुओं के बीच का मामला है और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा किसी भी राज्य के नगरपालिका कानून का सहारा लेकर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राजनयिक कार्रवाई के माध्यम से किया जाना चाहिए और ऐसा करने में विफल रहने पर उसे मजबूर किया जाना चाहिए। यह राज्य का एक शुद्ध और सरल कार्य है, और

यह उसका चरित्र है जब तक कि अधिग्रहण की प्रक्रिया विजय या समर्पण द्वारा पूरी नहीं हो जाती है। अब, इस प्रकार अर्जित किए गए क्षेत्रों के निवासियों की स्थिति यह है कि जब तक अधिग्रहण पूरा नहीं हो जाता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे उन क्षेत्रों के पूर्व संप्रभु के विषय हैं और उसके बाद वे नए संप्रभु के विषय बन जाते हैं। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि नई व्यवस्था में ये निवासी उन अधिकारों को अपने साथ नहीं रखते हैं जो उन्हें पूर्व संप्रभु की प्रजा के रूप में प्राप्त थे, और यह कि नए संप्रभु की प्रजा के रूप में, उनके पास केवल ऐसे अधिकार हैं जो उनके द्वारा दिए गए या मान्यता प्राप्त हैं; भारत के राज्य सचिव बनाम बाई राजबाई [(1)](एल.आर.42 आई.ए. 229), वजेसिंगजी जोरावर सिंहजी और अन्य बनाम राज्य सचिव [(2)](1924) एल.आर. 51 आई.ए. 357, 360) राज्य सचिव बनाम सरदार रुस्तम खान [(3)](1941) एल.आर.68 आई.ए. 109) और असरार अहमद बनाम दरगाह समिति, अजमेर [(4)](1947) ए.आई.आर.1947 पी.सी. 1) इसलिए, कानून के अनुसार, नए क्षेत्रों के अधिग्रहण की प्रक्रिया राज्य का एक निरंतर कार्य है जो नए संप्रभु द्वारा उन पर संप्रभु शक्तियों की धारणा पर समाप्त होता है और इसके बाद ही उन क्षेत्रों के निवासियों को उस संप्रभु के विषयों के रूप में अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में, जहां तक उन क्षेत्रों के निवासियों का संबंध है जो एक नए संप्रभु के प्रभुत्व के तहत आते हैं, नागरिकता का अधिकार तब शुरू होता है जब राज्य का अधिनियम समाप्त हो जाता है और इसलिए दोनों का सह-अस्तित्व नहीं हो सकता है।"

इससे यह पता चलता है कि नए संप्रभु द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों पर संप्रभु शक्तियों को ग्रहण करने से पहले किया गया कोई भी कार्य या घोषणा उन क्षेत्रों के निवासियों को उन अधिकारों को प्रदान करने वाले कानून के रूप में माना जा सकता है जो उनके न्यायालयों में उत्तेजित किए जा सकते हैं।

हालाँकि, यह अन्यथा है यदि नए संप्रभु का कार्य कानून के भीतर होना है और राज्य के किसी अधिनियम का सहवर्ती नहीं है। ऐसा ही एक मामला था वनपाल और अन्य बनाम भारत के राज्य सचिव (1)। उस मामले में एक सवाल यह था कि क्या राज्य का कोई अधिनियम था-एक ऐसा सवाल जिस पर अदालतें वैध रूप से विचार कर सकती हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि बेगम, जिनकी संपत्ति उनकी मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जब्त कर ली गई थी, एक संप्रभु राजकुमारी नहीं थी, बल्कि केवल एक जायदादार थी और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जागीर को फिर से शुरू करना राज्य का कार्य नहीं था, बल्कि एक कानूनी शीर्षक के तहत किया गया कार्य था। यह देखा गयाः-

> "इस मामले में सरकार का कार्य उन क्षेत्रों की मनमानी शक्ति द्वारा अभिग्रहण नहीं था जो उस समय तक किसी अन्य संप्रभु राज्य से संबंधित थे; यह उस कार्यकाल के कथित निर्धारण पर, एक विशेष कार्यकाल के तहत सरकार से पहले धारित भूमि की बहाली थी। कब्जा कानूनी शीर्षक के रंग के तहत लिया गया था, वह शीर्षक संप्रभु शक्ति का कार्यकाल के निर्धारण पर अपने क्षेत्रों के भीतर सभी भूमि को फिर से शुरू करने, और सार्वजनिक राजस्व को बनाए रखने या मूल्यांकन करने का निस्संदेह अधिकार था, जिसके तहत उन्हें असाधारण रूप से किराए से मुक्त रखा गया था। यदि कार्यकाल के जारी रहने या अन्य कारणों से, सरकार के इस शीर्षक का अपमान करते हुए किसी अधिकार का दावा किया जाता है, तो वह दावा, सरकार और उसके विषयों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी अन्य दावे की तरह, प्रथम दृष्टया भारत के नगर न्यायालयों द्वारा संज्ञेय होगा।"

इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य का कार्य एक विदेशी के खिलाफ संप्रभु शक्ति का प्रयोग है और न तो कानूनी रूप से स्थापित होने का इरादा है और न ही इसका उद्देश्य है। इस तरह का बचाव कानून के संदर्भ में कार्रवाई को उचित ठहराने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि कार्रवाई की वैधता या न्याय पर निर्णय देने के लिए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाता है।

अब हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या इस मामले में बचाव में याचिका का समर्थन करने के लिए आवश्यक तथ्य मौजूद थे। हमें यह निर्धारित करना चाहिए कि प्रत्यर्थी की उस तारीख को क्या स्थिति थी जब उसके खिलाफ विवादित आदेश पारित किया गया था। पूर्व भारतीय राज्यों के पूर्व शासकों की स्थिति का इस न्यायालय द्वारा एक से अधिक अवसरों पर विश्लेषण किया गया है और हमें लंबे समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 7 के कारण सर्वोच्चता समाप्त होने के बाद, जूनागढ़ का नवाब एक संप्रभु बन गया, लेकिन उसने सौराष्ट्र के अन्य शासकों की तरह विलय के एक दस्तावेज को निष्पादित करके नए डोमिनियन को स्वीकार नहीं किया। वह देश छोड़कर चला गया। जूनागढ़ की स्थिति इस प्रकार अद्वितीय थी और बाद में जो हुआ उसका वर्णन भारतीय राज्यों पर श्वेत पत्र में किया गया है, जिस पर बिना सबूत के एक संवैधानिक दस्तावेज के रूप में भरोसा करना प्रथागत हो गया है।

> "जूनागढ़ के नवाब के पाकिस्तान के लिए राज्य छोड़ने के बाद, नवाब की परिषद के अनुरोध पर 9 नवंबर, 1947 को भारत सरकार ने इस राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। जाहिर है, भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को जूनागढ़ के लोगों की पूरी मंजूरी थी क्योंकि फरवरी 1948 में जूनागढ़ और आसपास के छोटे राज्यों में हुए जनमत संग्रह के परिणामों से पता चला कि भारत में विलय के पक्ष

में मतदान लगभग सर्वसम्मत था। जिस अवधि के दौरान भारत सरकार ने राज्य का प्रभार संभाला था, उस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासक ने तीन लोकप्रिय प्रतिनिधियों की सहायता से राज्य के प्रशासन का संचालन किया। दिसंबर 1948 में, जूनागढ़ के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि राज्य का प्रशासन सौराष्ट्र सरकार को सौंप दिया जाए और जूनागढ़ के प्रतिनिधियों को सौराष्ट्र और जूनागढ़ राज्य के लिए एक सामान्य संविधान बनाने की दृष्टि से सौराष्ट्र राज्य की संविधान सभा में भाग लेने में सक्षम बनाया जाए। मानवदार, मंगरोल, बंटवा, बाबरियावाड़ और सरदारगढ़ के प्रतिनिधियों द्वारा इसी तरह के प्रस्तावों को अपनाया गया। तदनुसार, उपरोक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने की दृष्टि से काठियावाड़ राज्यों के शासकों द्वारा एक पूरक वाचा (परिशिष्ट 36) का निष्पादन किया गया था। 20 जनवरी, 1949 को सौराष्ट्र सरकार ने जूनागढ़ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। तदनुसार संविधान जूनागढ़ और इन राज्यों को सौराष्ट्र का हिस्सा मानता है।"

इससे यह प्रतीत होता है कि 9 नवंबर, 1947 और 20 जनवरी, 1949 के बीच भारत अधिराज्य द्वारा राज्य का कोई औपचारिक विलय नहीं किया गया था, हालांकि केंद्र सरकार अपने क्षेत्रीय आयुक्त, पश्चिमी भारत और गुजरात राज्य क्षेत्र के माध्यम से कानून और व्यवस्था बनाए रख रही थी और प्रशासन चला रही थी। 16 नवंबर, 1947 को प्रशासक द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी की गई थीः

सूचना

संख्या 09/1947

एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि 1944 का जूनागढ़ राज्य आदेश संख्या 568 रद्द कर दिया जाए। उक्त आदेश द्वारा बनाई गई राज्य परिषद को इसके द्वारा भंग कर दिया जाता है।

परिषद को किए जाने वाले किसी भी अधिनियम, नियमों, आदेशों, सम्मेलन, उपयोग आदि द्वारा आवश्यक कोई भी संदर्भ अब से प्रशासक, जूनागढ़ राज्य को दिया जाएगा, जिसमें परिषद और उसके सदस्यों द्वारा अब तक प्रयोग की गई सभी शक्तियां निहित होंगी।

जूनागढ़ एस डब्ल्यू शिवेशवरकर

14 नवम्बर, 1947 प्रशासक, जूनागढ़ राज्य"

उस तारीख से जूनागढ़ राज्य का प्रशासन भारत अधिराज्य के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासक के केंद्र में था। कड़ाई से कहें तो जूनागढ़ के लोग बहुत बाद तक डोमिनियन के नागरिक नहीं बने। अंतराल के दौरान वे विदेशी थे, भले ही वे भारत के साथ जुड़ना चाहते थे और जनमत संग्रह में लगभग सर्वसम्मति से खुद को व्यक्त किया था।

इस प्रकार जूनागढ़ राज्य के प्रशासन को ग्रहण करने में डोमिनियन का कार्य राज्य का एक शुद्ध और सरल कार्य था और राज्य के अधिनियम के समाप्त होने से पहले प्रशासक की कार्रवाई की गई थी।

प्रतिवादी ने हमारे सामने तर्क दिया कि राज्य के अधिनियम का सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं होता है। उनके अनुसार राज्य परिषद अस्तित्व में थी और उसने भारत अधिराज्य को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया था और सभी स्थानीय कानून अभी भी लागू थे। उन्होंने बताया कि सौराष्ट्र सिविल प्रक्रिया संहिता को 7 जुलाई, 1948 को एक अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था और इससे यह भी

साबित हुआ कि स्थानीय कानून लागू थे और प्रशासक क्षेत्रीय आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण के तहत निजी संपत्ति के साथ अपने व्यवहार में उनके अधीन थे। यह सब तथ्य से परे है और वास्तव में राज्य के कार्य की व्याख्या नहीं करता है जो हुआ था। राज्य के एक अधिनियम का सार संप्रभु शक्ति का प्रयोग है और यह नगरपालिका कानून के बाहर या सर्वोपरि सिद्धांतों पर मनमाने ढंग से किया जाता है। यह तथ्य कि संप्रभु निवासियों को अपने पुराने कानूनों और रीति-रिवाजों को बनाए रखने की अनुमति देता है, संप्रभु को उनके अधीन नहीं बनाता है और उन कानूनों के तहत सभी अधिकार संप्रभु की खुशी पर रखे जाते हैं। यह केवल तभी कहा जा सकता है जब संप्रभु को कानूनों के भीतर कार्य करने के लिए कहा जा सकता है कि राज्य का अधिनियम बचाव में एक याचिका का वहन करना बंद कर देता है। उस स्तर तक पहुँचने से पहले, सरकार मौजूदा कानूनों और अधिकारों और दायित्वों से प्रभावित हो सकती है, लेकिन उनके द्वारा शासित या बाध्य नहीं है। कैम्पबेल बनाम हॉल [(1)] कॉम्प 204;98 ई.आर.1945) रूडिंग बनाम स्मिथ [(2)] (हेग.कॉन.384; 161 ई.आर.774) विजय के दो मामले और ई.आई. कंपनी बनाम सैयद अली [(3)](7 एम.आई.ए. 555 एट 578) देखें। भारत का मईन आपराधिक कानून (चौथा संस्करण) ॥ पृष्ठ 119, 120 भी देखें जहां कानून का सारांश दिया गया है। यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि डोमिनियन ने पुराने अधिकारों को स्पष्ट रूप से या यहां तक कि मौन रूप से मान्यता दी थी, जिसे साबित करने का बोझ प्रत्यर्थी भारत के राज्य सचिव बनाम बाई राजबाई [(4)] (एल.आर. 42 आई.ए. 229) और वजे सिंह के मामले (5) (1924) एल.आर. 51 जे.ए. 357, 360) (ऑप. सिट.) पर था।

मामले के इस दृष्टिकोण में यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं है कि नवाब इस संपत्ति के संबंध में दाता को अधिकार प्रदान कर सकता था या नहीं। समान रूप से नवाब की अपने अनुदानों को फिर से शुरू करने या उनका अपमान करने की शक्तियों

और क्या डोमिनियन सरकार या उसके एजेंटों को समान या समान शक्तियां विरासत में मिली थीं, इसकी जांच भी निष्फल होगी। डोमिनियन सरकार की कार्रवाई राज्य का एक कार्य होने के नाते, प्रशासक का कार्य, चाहे वह मनमाना ही क्यों न हो, नगरपालिका अदालतों में न्यायोचित नहीं था और मुकदमा अच्छी तरह से स्थापित नहीं था।

इसलिए अपील की अनुमति दी जाती है। प्रत्यर्थी के मुकदमे को पूरे खर्च के साथ खारिज किया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।